

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)  
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 91/2019

- 1- प्रेमप्रकाश पुत्र बृजमोहन
- 2- प्रदीप कुमार पुत्र बृजमोहन  
समस्त जाति अहिर निवासीगण नावां तहसील नांवा जिला नागौर राज०।  
.....अपीलान्त

बनाम

- 1-तहसीलदार नावां, तहसील नांवा जिला नागौर, राज०।
- 2-पटवारी हल्का खारड़िया, तहसील नावां जिला नागौर राज०।  
.....रेस्पोजेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

- 1-श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी, व श्री गोविन्द कड़वा अधिवक्तागण अपीलान्त की ओर से।

अपील विरुद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा एल.आर.एक्ट 1956  
की धारा 91 बअनुवान सरकार बनाम प्रेमप्रकाश प्रकरण संख्या 04/2019  
न्यायालय तहसीलदार नांवा निर्णय दिनांक 02.07.2019

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

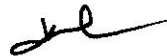
निर्णय

दिनांक : 05.03.21

{1} -यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नांवा के प्रकरण सं० 04/2019 बअनुवान पटवारी हल्का खारड़िया बनाम प्रेमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2019 के विरुद्ध पेश की है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खारड़िया ने अपीलान्त/अप्रार्थीगण के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार नांवा को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्त/अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर




  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना

207 रकबा 1520 वर्गमीटर किस्म गैम०मु० रास्ते पर डोल बनाकर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त/अप्रार्थीगण को राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त/अप्रार्थीगण द्वारा मौजा खारड़िया के खसरा नम्बर 207 रकबा 1520 वर्गमीटर किस्म गै० मु० रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा खारड़िया के खसरा नम्बर 207 रकबा 1520 वर्गमीटर गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 38/- अक्षरे अड़तीस रूपये कायम किया गया। पटवारी हल्का को अप्रार्थीगण के उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने व शास्ती वसुली हेतु आदेश दिये गए।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील दिनांक 18.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्त की अपील को दिनांक 28.08.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2018/386 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय का प्राप्त हुई।

{3} -वकील अपीलान्त की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्त ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:-



  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

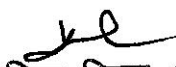
{3}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि तहसीलदार नावा द्वारा पूर्णरूप से विधि विरुद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है एवं जिस पर तहसीलदार नावा द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया है जबकी अपीलान्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

{3}(5) – यह है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मौके पर अन्य स्थान पर रास्ता है यदि उक्त कटाणी रास्ता का सीमाज्ञान कर सम्पूर्ण रास्ते को खुलवाया जाता है तभी सम्पूर्ण काश्तकारों को राहत मिलती है। केवल मात्र अपीलान्त के खेत में रास्ता खोल देने से उक्त रास्ता चालू नहीं हो सकता। उक्त रास्ता राधामोहन वगैरे ने भी बन्द कर रखा है। उनके द्वारा रास्ता खोलने पर ही उक्त रास्ता चालू स्थिति में आ सकता है इसके अलावा उक्त रास्ता चालू होने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा कोई कटाणी रास्ता बन्द नहीं किया हुआ है।

{3}(6) – यह है कि उक्त पत्रावली में पटवारी के कोई बयान नहीं लिये गये है। ही अपीलान्त को जवाब का समुचित अवसर दिया गया जवाब हेतु अवसर चाहा



  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीहवारा

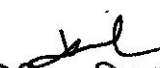
गया, जिस पर ना ही जवाब बन्द किया गया ना ही जवाब लिया गया । निर्णय के दिन अधिवक्ता अपीलान्ट को भी नहीं सुना गया तथा अपीलान्ट को भी अनुपस्थित करते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया गया एवं अपीलान्ट को दस्तावेज पेश करने का भी समय नहीं दिया गया जो कि न्याय की मंशा के विरुद्ध है। जिससे आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(7) - यह है कि अपीलान्ट का रास्ता की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।, इससे पूर्व अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का नाप चौक करवाया जाना आवश्यक है एवं उसके पश्चात ही अतिक्रमी माना जा सकता है ।

{4} - बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी खारड़िया की रिपोर्ट, जिसकी जाँच भू०अ०निरीक्षक मिठड़ी द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम खारड़िया, के खसरा नम्बर 207 रकबा 1520 वर्गमीटर किस्म गै० मु० रास्ता पर डोल लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थीगण दिनांक 26.6.2019 को स्वमं मय अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुवे, तथा जवाब हेतु समय चाहा, दिनांक 02.7.2019 को जवाब नहीं दिया तथा अनुपस्थित पाये गये। उक्त प्रकरण कटटाणी रास्ते पर अतिक्रमण से सम्बन्धीत है, जो राजकीय भूमि है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि में आती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं निर्णय का आदेश यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।




  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
जीड़वाना

:::: आदेश :::


अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील पर खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.07.2019 का यथावत रखा जाता है।



  
(रिषुपाल सिंह बुरडक)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
डी.डवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(रिषुपाल सिंह बुरडक)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
डी.डवाना (नागौर)